

राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिया गया फैसला 107 करोड़ रु. से राज्य में बनेंगे 100 पशु अस्पताल

केटी न्यूज/पटना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में हुई। इसमें कुल 14 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गई। इनमें नए पदों की स्वीकृति समेत कई अहम निर्णय हैं। जेनरल कैटेगरी से आने वाले लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस के तहत न्यायिक सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। राज्य भर में 100 पशु अस्पताल बनाने का फैसला सरकार ने लिया है। 107 करोड़ रुपए की राशि से इसका निर्माण करवाया जाएगा। इसमें आवास की भी सुविधा होगी। वहीं कैबिनेट ने नरकटियागंज के बीडीओ राघवेंद्र कुमार त्रिपाठी और मोतिहारी के तत्कालीन सहायक योजना पदाधिकारी सह प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी स्वामीनाथ मांझी को अनिवार्य रिटायरमेंट दिया है।

जिला उपभोक्ता फोरमों के लिए 30 पदों की स्वीकृति: कैबिनेट ने विज्ञान, प्राथमिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना में प्रशाखा पदाधिकारियों के पहले से स्वीकृत तीन पदों को प्रत्यर्पित करते हुए पदाधिकारियों-कर्मियों के 16 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। सरकार ने राज्य के विभिन्न जिला उपभोक्ता फोरमों के लिए अनुबंध के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिकों के 30 पदों की स्वीकृति दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए रिट याचिका पर इस संबंध में आदेश दिया था, जिसपर नीतीश मंत्रिमंडल ने यह स्वीकृति दी। नीतीश कैबिनेट ने परिवहन विभाग के तहत बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली 2023 के मद्देनजर



बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पर खर्च होंगे 67 करोड़

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि राज्य में 1135 पशु चिकित्सालय हैं, जिनमें से 657 के पास अपना भवन है। शेष 478 को अपना भवन देने की प्रक्रिया चल रही है। इनमें से 100 प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय-सह-आवास के भवन निर्माण के लिए एक अरब सात करोड़ 69 लाख रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना के भवनों के निर्माण एवं उपकरणों के लिए 66 करोड़ 93 लाख 11 हजार रुपये की स्वीकृति दी। राज्य मंत्रिमंडल ने विज्ञान, प्राथमिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों और राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के प्राचार्यों को भवन की मरम्मत एवं मेटेनंस मद में 10 लाख रुपये तक खर्च के लिए वित्तीय शक्तियां प्रदान की।

प्रमंडल स्तरीय ऐसे न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, उच्च वर्गीय

बिहार असैनिक सेवा भर्ती संशोधन मंजूरी

राज्य मंत्रिमंडल ने राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान, प्रयोगशाला सहायक (तकनीकी) संवर्ग नियमावली 2023 को स्वीकृति दी। इसके अलावा, सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली 2023 और बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) भर्ती संशोधन नियमावली को भी स्वीकृति दी।

समस्तीपुर में बनेगा आरओबी: कैबिनेट ने पथ निर्माण विभाग के तहत समस्तीपुर जिला अंतर्गत दलसिंहसराय याद के लेवल क्रॉसिंग 32ए के बदले पहुंच पथ सहित रेलवे ओवरब्रिज के लिए 97 करोड़ 20 लाख 83 हजार 800 रुपये सहित कुल 135 करोड़ एक लाख 81 हजार रुपये के अनुमानित लागत को प्रशासनिक स्वीकृति दी।

लिपिक, निम्नवर्गीय लिपिक एवं आशुलिपिक के सात-सात पदों की भी स्वीकृति दी है।

हमारा मकसद है लोगों को आगे बढ़ाना, कोई उपेक्षित न हो: सीएम

केटी न्यूज/पटना

जातीय गणना के आंकड़े जारी होने के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में नौ दलों को बुलाया गया था। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सीएम सचिवालय में हुई बैठक में जाति आधारित गणना के आंकड़ों पर चर्चा हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 से हम जाति आधारित गणना करने के लिये प्रयासरत थे। हम चाहते थे कि 2021 की जनगणना जो हर इस वर्ष में होती है, जातीय आधार पर हो। 18 फरवरी 2019 को बिहार विधानसभा एवं बिहार विधान परिषद् द्वारा जनगणना जातीय आधार पर करने हेतु केन्द्र से सिफारिश करने की संकल्प को सर्वसम्मति से पारित किया गया। 27 फरवरी 2020 को बिहार विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से केन्द्र सरकार से जनगणना 2021 जातीय आधार पर करने के अनुरोध का प्रस्ताव पारित किया गया। 23 अगस्त 2021 को सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ हमने प्रधानमंत्री से मिलकर जाति आधारित गणना करने का अनुरोध किया था। केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गयी। फिर हमने निर्णय लिया कि राज्य सरकार अपने संसदधनों से जाति आधारित गणना करावेंगी। 1 जून 2022 को विधानमंडल



के सभी 9 दलों की बैठक बुलाई गयी जिसमें सभी दलों के नेताओं ने जाति आधारित गणना पर अपनी सहमति दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति आधारित गणना की रिपोर्ट में सभी वर्गों की डिटेल जानकारी दी गयी है। पूरे तौर पर ठीक ढंग से सर्वे किया गया है। हर जाति की जानकारी दी गयी है। हर परिवार की आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति की जानकारी ली गयी है। अब जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद सभी दलों की राय से हमलोग राज्य के हित में इस पर काम करेंगे। राज्य के सभी लोगों के उत्थान के लिये इस पर आगे विचार विमर्श कार्य किया जायेगा। हमलोगों का मकसद है लोगों को आगे बढ़ाने का, जो पीछे है, उपेक्षित है, उसकी उपेक्षा न हो। सब आगे बढ़ें। इन सब चीजों को ही ध्यान में रखकर काम किया जायेगा। हमलोगों का

मकसद है सभी का विकास करना, उन्हें आगे बढ़ाना है। राज्य के हित में सबकी सहमति से कार्य करेंगे।

बीजेपी ने गणना पर जताई आपत्ति: बीजेपी के नेता और 'हम' संयोजक जीतन राम मांझी ने मौजूदा जाति आधारित गणना में कई खामियों को सरकार के सामने रखा, जिस पर मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लेते हुए सम्बंधित अधिकारी को उसे दूर करने की बात कही। बैठक में सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े नहीं रखे गए, जिसका बीजेपी ने विरोध किया है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों को विधानसभा में सत्र के दौरान रखा जाएगा। बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा और हरि सहनी शामिल हुए। वहीं, महामठबंधन की तरफ से छह और एनडीए की

तरफ से दो, एक एआईएमआईएम के नेता बैठक में शामिल हुए। नौ पार्टियों के नेता बैठक में शामिल हुए। बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने कहा कि टुकड़े-टुकड़े में रिपोर्ट क्यों जारी कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि एक बार आर्थिक रिपोर्ट भी जारी हो। उन्होंने यह भी कहा कि समाज के जिन लोगों को जातीय गणना रिपोर्ट से आपत्ति है उनको आपत्ति का अवसर मिलना चाहिए। विजय सिन्हा ने कहा कि हमलोगों ने अपनी आपत्ति को दर्ज की बताया कि ये सब कमियां हैं। जो आपत्ति है इसका निष्पादन होना चाहिए। हमने कहा कि इसमें आपत्ति दर्ज करने का अवसर मिलना चाहिए।

विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरि सहनी ने इस जातीय गणना की रिपोर्ट को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस तरह कोई परीक्षा में एवरेज मार्किंग किया जाता है, उसी तरह ही इसमें किया गया है। किसी को घटा कर किसी को बढ़ा दिया गया, इससे स्थिति यह हो गई कि कहीं खुशी तो कहीं गम की स्थिति है। एक ही जाति को कई वर्गों में बांट दिया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने सोमवार को बहुप्रतीक्षित जाति आधारित गणना के निष्कर्ष जारी किए, जिसमें खुलासा हुआ कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) राज्य की कुल आबादी का 63 प्रतिशत हैं।

एक अक्टूबर को हुई सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द सात व 15 को होनेवाली परीक्षा की गई स्थगित

केटी न्यूज/पटना

बिहार में एक अक्टूबर को हुई सिपाही भर्ती की परीक्षा रद्द हो गई है। केंद्रीय चयन पर्वद की ओर से मंगलवार को इस संबंध में पत्र जारी कर सूचना दी गई है। बताया गया है कि दोनों पालियों की परीक्षा कैलेंडर की गई है। वहीं सात और 15 अक्टूबर को जो परीक्षा होने वाली थी उसे भी अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

एजमा रद्द होने के पीछे साफ वजह है कि पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद इस तरह का निर्णय लिया गया है। बोर्ड ने भी नोटिस में इन्हें चीजों का जिक्र किया है। जारी पत्र में कहा गया है कि एक

अक्टूबर को दोनों पालियों में लिखित परीक्षा में काफी संख्या में नकल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और चीट-पुर्जों के साथ राज्य के विभिन्न जिलों से अभ्यर्थी पकड़े गए थे। इसके अलावा यह भी जानकारी मिली कि प्रश्नों के तथाकथिक उत्तर सादे पन्ने पर सीरियल नंबर के साथ लिखकर मोबाइल एवं अन्य तरीकों से अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कर लिए गए हैं।

संगठित गिरोह का हो सकता है काम: जारी नोटिस में यह कहा गया है कि विभिन्न परीक्षा केंद्रों में काफी संख्या में अभ्यर्थी उत्तरों की नकल करते हुए और चीट-पुर्जों के साथ पकड़े गए थे। इन सबके खिलाफ मामला दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। वर्तमान में ये सभी मामले

अनुसंधान में हैं, लेकिन दो अक्टूबर को दोपहर ऐसे मामलों के संबंध में और अधिक जानकारी मिली जिससे पता चलता है कि इस प्रकार की क्रियाकलाप किसी सुनिश्चित तरीके से संगठित गिरोह द्वारा किया गया प्रतीत होता है।

बता दें कि पटना के कंकड़वाग से पेपर लीक की खबर सामने आई थी। रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज से पुलिस ने छह अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया था। सूत्रों के अनुसार इनमें से पांच के पास बरामद आंसर-की प्रश्न पत्र से मैच हुए हैं। वहीं 02 अक्टूबर को सिपाही भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष एसके सिंघल ने कहा था कि परीक्षा पूरी तरह से कदाचार मुक्त हुई है।

गया पहुंचे पंडित धीरेंद्र शास्त्री खास लोगों ने सुना प्रवचन

केटी न्यूज/पटना

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री तीन दिवसीय प्रवास पर गया पहुंचे हैं। सोमवार की शाम धीरेंद्र शास्त्री गया पहुंचे थे, जहां बीजेपी सांसद मनोज तिवारी समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया। पहली बार पटना के तरेत में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया था। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बोधगया में स्थिति रिसॉर्ट में तीन दिनों तक ठहरेंगे। सोमवार की देर रात तक रिसॉर्ट के हॉल में धीरेंद्र शास्त्री के द्वारा पितृ पक्ष में पितृ दोष निवारण के लिए प्रवचन का

आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सिर्फ खास श्रद्धालु ही शामिल हो सके। इस प्रवचन में आम लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं थी।

दरअसल, गया में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम आयोजित होने वाला था। तीन दिनों के भीतर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का दिव्य दरबार लगना था, इसके साथ ही साथ वे हनुमत कथा का भी पाठ करने वाले थे लेकिन कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण धीरेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम रद्द हो गया था। हालांकि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत धीरेंद्र शास्त्री गया पहुंचे हैं, यहां तीन दिनों तक प्रवास के दौरान वे अपने पूर्वजों का पिड़दान करेंगे।



GYAN JYOTI PUBLIC SCHOOL

Affiliated to CBSE NEW Delhi (10+2)

Rupsager, Main Road, Nawangar Buxar (Bihar)

Contact No - 6200727438, 7004289776, 7654245005 | Email - gips2011@Yahoo.in, gyanjyotipublicschool.in



विद्यालय में छात्रों के लिए अत्याधुनिक सुविधा

- असम, बंगाल व दार्जिलिंग के कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक
- स्मार्ट क्लासेज आडियो एवं वीडियो से कक्षाओं का संचालन
- अत्याधुनिक विज्ञान व कंप्यूटर की प्रयोगशालाएं
- सुव्यवस्थित पुस्तकालय
- खेलकूद, योग, नैतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा का कुशल ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण
- बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक क्लास सीसीटीवी कैमरे से लैस
- बच्चों के लिए हैप्पीनेस क्लासेज
- कराटे व स्काउट एंडगाइड का कुशल ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण

